

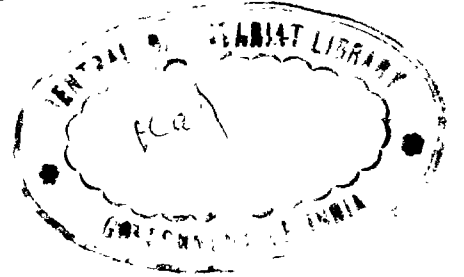


# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 190 ]  
No. 190]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 31, 2000/चैत्र 11, 1922  
NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 31, 2000/CHAITRA 11, 1922

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2000

सा०का०नि० 275(अ).—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

“सं० आ० 177”

संविधान (राजस्व वितरण) सं० 2 आदेश, 2000

राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 275 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात् निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात् :—

1. इस आदेश का संक्षिप्त नाम (राजस्व वितरण) सं० 2 आदेश, 2000 है।
2. साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10), इस आदेश के निर्वचन के लिए उसी प्रकार लागू होगा जिस प्रकार वह किसी केन्द्रीय अधिनियम के निर्वचन के लिए लागू होता है।
3. (1) अनुच्छेद 275 के खंड (1) के उपबंधों के अनुसार 1 अप्रैल, 1999 को प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्ष में, निम्नलिखित राजस्व सहायता अनुदान के रूप में भारत की संचित निधि पर भारित होगा—

(क) पंचायती राज संस्थाओं के लिए अनुदानों के लिए नीचे सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट राज्य में से प्रत्येक राज्य के सामने उक्त सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट राशियां,—

सारणी

राज्य	रुपए लाख में
(1)	(2)
आन्ध्र प्रदेश	18237.96
गोवा	73.50
गुजरात	13201.00
हरियाणा	5681.50
हिमाचल प्रदेश	1206.00
जम्मू-कश्मीर	2584.00
कर्नाटक	11089.00
केरल	4471.00
मध्य प्रदेश	11085.07
महाराष्ट्र	4338.00
मणिपुर	116.00
मेघालय	108.00
मिजोरम	73.00
नागालैंड	58.50
उड़ीसा	12561.50
पंजाब	1291.50
राजस्थान	6612.00
सिक्किम	106.00
तमिलनाडु	7184.00
त्रिपुरा	174.50
उत्तर प्रदेश	9494.00
पश्चिमी बंगाल	22925.00 :

परंतु किसी राज्य सरकार द्वारा ऊपर विनिर्दिष्ट राशियां उक्त वित्तीय वर्ष में पंचायती राज संस्थाओं को संदत्त की जाएंगी और ये राशियां राज्य सरकार से पंचायती राज संस्थाओं को दी जा रही राशियों के अतिरिक्त होंगी :

परंतु यह और कि ऊपर विनिर्दिष्ट राशियां, पंचायती राज संस्थाओं द्वारा दसवें वित्त आयोग की रिपोर्ट के अध्याय 10 में यथा अंतर्विष्ट उसकी सिफारिशों के अनुसार और केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में राज्य सरकारों को अनुदानों के उपयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए पुनरीक्षित दिशा-निर्देशों के अनुसार व्यय की जाएंगी ;

(ख) शहरी स्थानीय निकायों को अनुदानों के लिए नीचे सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट राज्यों में से प्रत्येक के सामने उक्त सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट राशियां :-

सारणी	
राज्य	रु० लाख में
(1)	(2)
आन्ध्र प्रदेश	2271.70
गुजरात	4637.50
हिमाचल प्रदेश	51.00
जम्मू-कश्मीर	831.50
कर्नाटक	3510.00
केरल	635.00
मध्य प्रदेश	3549.36
महाराष्ट्र	5816.00
मिजोरम	10.00
उड़ीसा	477.00
पंजाब	1338.75
राजस्थान	1079.00
सिक्किम	40.50
तमिलनाडु	2888.00
पश्चिमी बंगाल	2558.48 :

परंतु किसी राज्य सरकार द्वारा ऊपर विनिर्दिष्ट राशियां उक्त वित्तीय वर्ष में शहरी स्थानीय निकायों को संदत्त की जाएंगी और ये राशियां राज्य सरकार द्वारा शहरी स्थानीय निकायों को दी जा रही राशियों के अतिरिक्त होंगी :

परंतु यह और कि ऊपर विनिर्दिष्ट राशियां, शहरी स्थानीय निकायों द्वारा दसवें वित्त आयोग की रिपोर्ट के अध्याय 10 में यथा अंतर्विष्ट उसकी सिफारिशों के अनुसार और केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में राज्य सरकारों को अनुदानों के उपयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए पुनरीक्षित दिशा-निर्देशों के अनुसार व्यय की जाएंगी ।

(2) उपपैरा (1) के अधीन संदेय कोई राशि या राशियां अनुच्छेद 275 के खंड (1) के परंतुकों में से प्रत्येक के अधीन राज्यों को संदेय राशि या राशियों के अतिरिक्त होंगी ।

के०आर० नारायणन,

राष्ट्रपति

[ फा०सं० 19(2)/2000-वि-1 ]

रघुबीर सिंह, सचिव

**MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS****(Legislative Department)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 31st March, 2000

**G.S.R. 275(E).**—The following Order made by the President is published for general information :—

**“C.O. 177”****The Constitution (Distribution of Revenues) No. 2 Order, 2000**

In exercise of the powers conferred by article 275 of the Constitution, the President, after having considered the recommendations of the Finance Commission, hereby makes the following Order, namely :—

1. This Order may be called the Constitution (Distribution of Revenues) No. 2 Order, 2000.

2. The General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), shall apply for the interpretation of this Order as it applies for the interpretation of a Central Act.

3 (1) In accordance with the provisions of clause (1) of the article 275, there shall be charged on the Consolidated Fund of India, in the financial year commencing on the 1st day of April, 1999, as grants-in-aid of the revenues of—

(a) each of the States specified in column (1) of the Table below, the sums specified against it in column (2) of the said Table towards grants for Panchayati Raj Institutions :—

Table

State	(Rupees in Lakhs)
(1)	(2)
Andhra Pradesh	18237.96
Goa	73.50
Gujarat	13201.00
Haryana	5681.50
Himachal Pradesh	1206.00
Jammu and Kashmir	2584.00
Karnataka	11089.00
Kerala	3371.00
Madhya Pradesh	11085.07
Maharashtra	4338.00
Manipur	116.00
Meghalaya	108.00
Mizoram	73.00
Nagaland	58.50
Orissa	12561.50
Punjab	1291.50
Rajasthan	6612.00
Sikkim	106.00
Tamil Nadu	7184.00
Tripura	174.50
Uttar Pradesh	9494.00
West Bengal	22925.00

Provided that the sums specified above shall be paid to the Panchayati Raj Institutions in the said financial year by a State Government and these sums shall be in addition to the sums flowing to the Panchayati Raj Institutions from the State Government:

Provided further that the sums specified above shall be expended by Panchayati Raj Institutions as per the recommendations of the Tenth Finance Commission contained in Chapter X of its report and in the revised guidelines issued by the Central Government for utilisation of the grants from that Government to the State Governments in this regard;

(b) each of the States specified in column (1) of the Table below, the sums specified against it in column (2) of the said Table towards grants for Urban Local Bodies:—

TABLE

State	(Rupees in lakhs)
(1)	(2)
Andhra Pradesh.	2271.70
Gujarat ..	4637.50
Himachal Pradesh.	51.00
Jammu and Kashmir	831.50
Karnataka	3510.00
Kerala .	635.00
Madhya Pradesh ..	3549.36
Maharashtra .	5816.00
Mizoram.	10.00
Orissa	477.00
Punjab	1338.75
Rajasthan ..	1079.00
Sikkim	40.50
Tamil Nadu	2888.00
West Bengal	2558.48:

Provided that the sums specified above shall be paid to the Urban Local Bodies in the said financial year by a State Government and these sums shall be in addition to the sums flowing to the Urban Local Bodies from the State Government:

Provided further that the sums specified above shall be expended by Urban Local Bodies in terms of the recommendations of the Tenth Finance Commission as contained in Chapter X of its report and in the revised guidelines issued by the Central Government for utilisation of the grants from that Government to the State Governments in this regard.

(2) Any sum or sums payable under sub-paragraph (1) shall be in addition to any sum or sums payable to the States under each of the provisos to clause (1) of article 275.

K.R. NARAYANAN,  
President.

[F.No. 19(2)/2000-V-I]  
RAGHBIR SINGH, Secy.

95161/2000-2

